



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 209]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 14, 2018/ज्येष्ठ 24, 1940

No. 209]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 14, 2018/JYAISTHA 24, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2018

मामला सं. (ओ.आई.) 10/2018

**विषय - इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सैकरिन" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच की शुरुआत**

**फा. सं. 06/13/2018-डीजीएडी.**—मै. स्वाति पेट्रो प्रोडक्ट्स प्रा. लि. (जिसे आगे याचिकाकर्ता/आवेदक कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें इंडोनेशिया के मूल की अथवा वहां से निर्यातित सैकरिन (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

**क. विचाराधीन उत्पाद**

2. विचाराधीन उत्पाद "सैकरिन अपने सभी रूपों में" है (जिसे आगे इंडोनेशिया के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है)।

निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया है :-

"सैकरिन एक गैर-न्यूट्रिटिव स्वीटनर है और उसे गन्ने की चीनी का कम कैलोरी वाला प्रतिस्थापक माना जाता है। प्राथमिक रूप से दो प्रकार के सैकरिन होते हैं अर्थात् विलेय और अविलेय। बाजार शब्दावली में विलेय सैकरिन को सोडियम सैकरिन कहा जाता है जबकि अविलेय सैकरिन को सैकरिन या सैकरिन एसिड कहा जाता है। सोडियम सैकरिन के अलावा, सैकरिन के अन्य रूप हो सकते हैं जैसे कैल्शियम और जिंक सैकरिन। सैकरिन को दो भौतिक रूपों में उत्पादित किया जाता है अर्थात् दानेदार और पाउडर। सोडियम सैकरिन को दानेदार रूप में उन स्थितियों में प्रयोग किया जाता है जहां सैकरिन घुल जाती है, पाउडर रूप जिसे पीसा और स्प्रे ड्राई किया जाता है को शुष्क मिश्रणों और भेषजों में प्रयोग किया जाता है। यह जल में थोड़ा विलेय होता है। सैकरिन का अविलेय रूप अनेक भेषजों और चिकित्सीय अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाता है। सैकरिन को अनेक

उद्योगों में प्रयोग किया जाता है जैसे खाद्य और पेय, पर्सनल केयर उत्पाद, टेबल टाप स्वीटनर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ब्राइटनर्स, भेषज आदि। सैकरिन चीनी से 500 से अधिक गुना मीठी होती है। सैकरिन की सभी किस्में वर्तमान जाँच के दायरे के भीतर हैं..."

सैकरिन को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अधीन उपशीर्ष सं. 29251100 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और इस जाँच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

### **ख. समान वस्तु**

**3. समान वस्तु के संबंध में नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-**

"समान वस्तु" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जाँच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

4. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सैकरिन और संबद्ध देश से निर्यातित सैकरिन में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सैकरिन और संबद्ध देश से आयातित सैकरिन तकनीकी विशेषताओं, उनके समान अंतिम प्रयोगों, उनकी वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता और टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सैकरिन को पाटनरोधी नियमावली के अनुसार संबद्ध देश से आयातित सैकरिन के समान वस्तु माना जाना चाहिए।

5. इसलिए वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ, भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के "समान वस्तु" माना है।

### **ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति**

6. यह याचिका मै. स्वाति पेट्रो प्रोडक्ट्स प्रा. लि. द्वारा भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादक के रूप में दायर की गई है। याचिका में दी गई सूचना के अनुसार, भारत में संबद्ध वस्तु के अन्य उत्पादक भी हैं अर्थात् मै. श्री वरदायनी कैमिकल इंडस्ट्रीज प्रा. लि., ए. एस. केमोफार्मा प्रा. लि., मै. ब्लू सर्किल आर्गेनिक्स प्रा. लि. और विष्णु कैमिकल्स लि. हैं। तथापि, मै. श्री वरदायनी कैमिकल इंडस्ट्रीज प्रा. लि., ए. एस. केमोफार्मा प्रा. लि. और मै. ब्लू सर्किल आर्गेनिक्स प्रा. लि. ने याचिका का समर्थन किया है।

7. याचिकाकर्ता संबद्ध देश में पीयूसी के किसी निर्यातक या उत्पादक से संबंधित नहीं है।

अतः, प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि मै. स्वाति पेट्रो प्रोडक्ट्स प्रा. लि. जो वर्तमान में भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का प्रमुख उत्पादक है और कुल घरेलू उत्पादन में उसका "प्रमुख हिस्सा" बनता है और वह नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है और वह संबंधित नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार योग्यता के मापदंडों को भी पूरा करता है।

### **घ. शामिल देश**

8. वर्तमान जाँच में शामिल देश इंडोनेशिया है।

### **ङ. सामान्य मूल्य**

9. याचिकाकर्ता ने संबद्ध देश के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमत के बारे में सूचना/साक्ष्य प्राप्त करने के सभी प्रयास किए थे। तथापि, घरेलू उद्योग संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु की कीमतों की समान सूचना और साक्ष्य प्राप्त करने में अक्षम रहा था।

10. तदनुसार, याचिकाकर्ता ने भारत में उत्पादन लागत के आधार पर संबद्ध देश के लिए सामान्य मूल्य का दावा किया है जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और याचिकाकर्ता के खपत मानकों पर विचार करते हुए विधिवत रूप से समायोजित किया गया है। इसके अलावा, बिक्री लागत के लिए याचिकाकर्ता ने तर्कसंगत लाभ पर विचार किया है।

11. अतः, प्राधिकारी ने जाँच शुरूआत के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित सामान्य मूल्य के साथ आगे की कार्रवाई की है।

### **च. निर्यात कीमत**

12. प्राधिकारी ने भारत में आयातों की मात्रा और मूल्य का आकलन करने के लिए फरवरी 2018 तक के डीजीसीआईएंडएस के आकड़ों को प्रयोग करके निर्यात कीमत निर्धारित की है। कारखाना-द्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए मालभाड़े, बीमा, कमीशन, बैंक प्रभारों और पतन व्ययों के लिए कीमत समायोजनों का दावा किया गया है। तथापि प्राधिकारी द्वारा यदि निर्यातक के आकड़े प्रस्तुत और सत्यापित किए जाते हैं तो प्राधिकारी उन पर भरोसा करना चाहेंगे।

### **छ. पाटन मार्जिन**

13. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर निर्यात कीमत के साथ की गई है जिससे संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के संबंध में भारी पाटन मार्जिन का पता चलता है। इस प्रकार अनुमानित पाटन मार्जिन संबद्ध देश के लिए निर्धारित न्यूनतम

सीमा से अधिक है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना-द्वारा निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया पता चलता है कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

#### **ज. क्षति और कारणात्मक संबंध**

14. घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है। याचिकाकर्ता ने कथित पाटित आयातों के कारण हुई क्षति के विभिन्न मापदंडों जैसे पाटित आयातों की समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से बढ़ी हुई मात्रा, कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री और लाभ, नियोजित पूंजी पर आय, नकद प्रवाह और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर भारी प्रतिकूल परिणामी प्रभाव के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उठायी जा रही क्षति संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण हो रही है जो पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराता है।

#### **झ. पाटनरोधी जांच की शुरूआत**

15. और यतः प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं, इसलिए प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

#### **ञ. जांच अवधि (पीओआई)**

16. जांच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च, 2018 (12 महीने) तक की है। तथापि क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ पूर्ववर्ती तीन वर्षों अर्थात् अप्रैल 2014 – मार्च, 2015, अप्रैल 2015 – मार्च, 2016, अप्रैल 2016 – मार्च, 2017 और जांच अवधि के आकड़ों पर विचार किया जाएगा।

#### **सूचना प्रस्तुत करना**

17. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उसके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, भारत में उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों व प्रयोक्ताओं को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने और निम्नलिखित पते पर प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया है:

**निर्दिष्ट प्राधिकारी**  
**व्यापार उपचार महानिदेशालय**  
**वाणिज्य विभाग**  
**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**  
**चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,**  
**5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001**

18. कोई अन्य हितवद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षों को उसे उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

#### **ट. समय-सीमा**

19. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजा जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

20. सभी हितवद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरूआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की जरूरत या अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

**ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

21. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर “गोपनीय” या “अगोपनीय” अंकित होना चाहिए और उनके साथ साफ्ट प्रति भी होनी चाहिए।

22. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। समस्त हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।

23. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

24. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

25. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

26. किसी सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

**ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

27. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

**ढ. असहयोग**

28. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th June, 2018

Case No. (O.I.) 10/2018

**Subject: Initiation of Anti-Dumping investigation concerning imports of “Saccharin” originating in or exported from Indonesia.**

**F. No. 6/13/2018- DGAD.**—M/s Swati Petro Products Pvt Limited (hereinafter referred to as the Petitioner/ Applicant) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as The Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for imposition of Anti-dumping duty on imports of Saccharin (hereinafter referred to as the “subject goods”) originating in or exported from Indonesia.

**A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION**

2. The product under consideration in the present investigation is “Saccharin in all its form” [hereinafter also referred to as ‘Subject Goods’ originating in or exported from Indonesia.

The Designated Authority has considered PUC as under:-

“Saccharin is a non-nutritive sweetener and considered to be low calorie substitute for cane sugar. Primarily there are two types of Saccharin i.e. soluble and insoluble. In market parlance soluble saccharin is called sodium saccharin whereas insoluble saccharin is called saccharin or saccharin acid. Apart from sodium saccharin, saccharin can have other variants such as calcium and zinc saccharin. Saccharin is produced in two physical forms, viz. granular and powder. Sodium saccharin in granular form is used in situations where saccharin will be dissolved, the powder form which has been grounded and spray dried is used in dry mixes and pharmaceuticals. It is slightly soluble in water. Insoluble form of saccharin is used in many pharmaceutical and medical applications. Saccharin is used in a variety of industry such as food and beverage, personal care products, table top sweeteners, electroplating brighteners, pharmaceuticals, etc. Saccharin is more than 500 times sweeter than sugar. All forms of Saccharin are within the scope of the present investigation...”

Saccharin is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-headings No. 29251100. However, Customs classifications are indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.

**B. LIKE ARTICLE**

3. Rule 2(d) with regard to like article provides as under: -

*"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;*

4. There is no known difference in Saccharin produced by the domestic industry and Saccharin exported from the subject country. Saccharin produced by the domestic industry and imported from the subject country is comparable in terms of technical characteristics, their similar end uses, their commercial substitutability and tariff classification. Saccharin produced by the domestic industry should be treated as like article to the Saccharin imported from subject country in accordance with the Anti-Dumping Rules.

5. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject country.

**C. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING**

6. The petition has been filed by M/s Swati Petro Products Pvt Limited as producer of the subject goods in India. As per the information given in the petition there are other producers also of the subject goods in India namely M/s Shree Vardayini Chemical Industries Pvt Ltd, A. S Chemopharma Pvt Ltd, M/s Blue Circle Organics Pvt Ltd and Vishnu Chemicals Ltd. However, M/s Shree Vardayini Chemical Industries Pvt Ltd, A. S. Chemopharma Pvt Ltd and M/s Blue Circle Organics Pvt Ltd have supported the petition.

7. The petitioner is not related to any exporter or producer of the PUC in the subject country.

The Authority, therefore, determines that M/s Swati Petro Products Pvt who presently is the major producer of subject goods in Indian market and accounts for “major proportion” of the total domestic production and constitutes an eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b) and also satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

**C. COUNTRY INVOLVED**

8. The country involved in the present investigation is Indonesia.

**D. NORMAL VALUE**

9. The petitioner has made all efforts to extract information/evidence on the price of the subject good in the domestic market of the subject country. However, the Domestic industry was unable to obtain the same information or evidence of prices of subject goods in the subject country.

10. Accordingly, the petitioner has claimed the Normal Value for subject country on the basis of cost of production in India, duly adjusted for selling, general and administrative expenses and considering the consumption norms of the petitioners. Further to the cost of sales, the petitioner has considered reasonable profit.

11. The Authority has, therefore, for the purpose of the initiation, decided to proceed with the normal value as determined by the Authority on the basis of prima facie evidence submitted by the petitioner.

E. **EXPORT PRICE**

12. The Authority has determined Export price using DGCIS data till February 2018 to assess the volume and value of imports in India. Price adjustments have been claimed on account of freight, insurance, commission, bank charges and port expenses to arrive at net export price at ex-factory level. However, the Authority would like to rely on data of exporter in case the same are furnished and verified.

F. **DUMPING MARGIN**

13. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which shows significant dumping margin in respect of the subject goods from the subject country. The dumping margin so estimated is above de-minimis limits for the subject country. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods from the subject country is significantly higher than the ex-factory export price, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country.

G. **INJURY AND CAUSAL LINK**

14. Information furnished by the petitioner has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The petitioner has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of alleged dumping in the form of increase in volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, price undercutting, price depression, price underselling and consequent significant adverse impact on the domestic industry in terms of profits, return on capital employed, cash flow and market share of the domestic industry. There is sufficient prima facie evidence of 'injury' being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from subject country to justify initiation of an anti-dumping investigation.

H. **INITIATION OF THE ANTI-DUMPING INVESTIGATION**

15. And whereas, the Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country; injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exists to justify initiation of an anti-dumping investigation, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

I. **PERIOD OF INVESTIGATION (POI)**

16. The period of investigation (POI) is 1<sup>st</sup> April 2017 to 31<sup>st</sup> March 2018 (12 months). However, for the purpose of analysing injury, the data of previous three years, i.e. Apr'14-Mar'15, Apr'15-Mar'16, Apr'16-Mar'17 and the POI will be considered.

J. **SUBMISSION OF INFORMATION**

17. The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**The Designated Authority,  
Directorate General of Trade Remedies,  
Department of Commerce  
Ministry of Commerce & Industry,  
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street, New Delhi -110001.**

18. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to submit a non-confidential version of the same to be made available to the other parties.

**K. TIME LIMIT**

19. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.

20. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the Domestic Industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

**L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS**

21. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/ submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non- Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page and accompanied with soft copies.

22. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and two (2) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

23. For information claimed as confidential, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

24. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

25. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

26. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**M. INSPECTION OF PUBLIC FILE**

27. In terms of rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidences submitted by other interested parties.

---

N. **NON-COOPERATION**

28. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority